(ग) सचिव, योजना आयोग ने शाहपुर-कन्दी परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विचार -विमर्श के लिये 26 जुलाई, 1988 को एक बैठक ली थी और 10 मई, 1984 को हुए समझौते के अनुसार मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजे बगैर हरियाणा और राजस्थान शाहपुर-कन्दी परियोजना के क्रियान्वयन के लिये सहमत नहीं हुए थे इसलिये परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ।

राजस्थान में बिजली की स्थिति

1611. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में बिजली की मांग कितनी है और इसकी आवश्यकता की कितनी प्रतिशत बिजली पूरी की जा रही है ;

(ख) राजस्थान में चल रही परियोजनाओं से कितने प्रतिशत बिजली उसे मिल रही है और अन्य राज्यों से बिजली की पूर्ति हो रही है और उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान में कौन-कौन सी नई विद्युत परियोजनायें लगाई जाएंगी और उनकी क्षमता कितनी-कितनी होगी ; और

(ङ) इस समय उस राज्य में स्थित कौन-कौन सी विद्युत परियोजनायें सुचारू रूप से कार्य कर रही है, कौन-कौन सी परियोजनायें खराबियों के कारण बंद पड़ी हैं तथा वे कितने दिन चालू रहीं, और कितने दिन बन्द रहीं, और प्रचालन अवधि के दौरान उनका संयंत्र उदभार गुणक कितना-कितना रहा ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अप्रैल, 89--फरवरी, 90 की अवधि के दौरान राजस्थान की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता 9557 मिलियन यूनिट थी तथा इसकी 97% आवश्यकता की पूर्ति की गई थी ।

(ख) अप्रैल, 89--फरवरी, 90 के दौरान राजस्थान में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. राजस्थान में स्थित परियोजनाओं से	45%
2. उत्तरी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से	26%
3. भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड से	26%
4. मध्य प्रदेश की संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजना से	1%
5. पंजाब से	2%

(ग) और (घ) आठवीं योजनावधि के दौरान निधियों एवं निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राजस्थान में अनन्तिम रूप से 223.4 मैगावाट क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है । इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र में प्रतिस्थापित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में भी राजस्थान को अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी । तथापि 8वीं योजना के अंत में विद्युत की मांग इसकी उपलब्धता से अधिक होने के कारण राज्य द्वारा विद्युत की कमी का अभी सामना किए जाने की संभावना है ।

(ङ) अपेक्षित सूचना अनुपत्र में दी गई है । (**देखिए** परिशिष्ट 153, अनुपत्र सं० 69)

राजस्थान की लम्बित ताप विद्युत परियोजनायें

1612. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपादन के बाद भी

राजस्थान में अनुमानतः 46 से 42 प्रतिशत तक विद्युत की कमी बनी रहेगी ; और यदि हां, तो राजस्थान मे विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान में विद्युत की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 1984 मे तकनीकी आर्थिक अनुमोदन हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को 4 विद्युत ताप परियोजनायें प्रस्तुत की थीं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं को आठवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या धौलपुर ताप विद्युत परियोजना इसलिए अस्वीकार कर दी गई है, क्योंकि इससे "ताज महल" पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; यदि हां, तो सरकार किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राजस्थान में 8वीं योजना के अंत में कुल मिलाकर लगभग 34.9 प्रतिशत तक की कमी होने का अनुमान है जबकि देश में 38,369 मैगावाट क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है ।

राज्य मे विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में से शामिल हैं ; नई क्षमताओं को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता का इष्टतम सदुपयोग करना, दक्ष प्रबंध परिषण और वितरण हानियों को कम करना । इसके अलावा, क्षेत्र के केंद्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से भी राजस्थान अपने हिस्से की विद्युत पाने का हकदार होगा । जहाँ तक सम्भव होता है राजस्थान की पड़ौसी राज्यों प्रणालियों द्वारा भी सहायता की जाती है ।

(ख) और (ग) राजस्थान से प्राप्त हुई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम और क्षमता	वर्तमान स्थिति
1.	सूरतगढ़ 2×210 मे.वा.	इस परियोजना के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्य मूल्यांकन अभिकरण के साथ विचार किया जा रहा है और कोयला लिंकेज सुनिश्चित किये जाने के बाद ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु इस पर विचार किया जा सकेगा ।
2.	धौलपुर 3×210 मे.वा.	पर्यावरण विभाग ने प्रस्तावित स्थल को अस्वीकृत कर दिया था, ताजमहल पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी । तदनुसार, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को वैकल्पिक स्थल का पता लगाने और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने को कहा गया था । उक्त रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई ।
3	मण्डलगढ़ 3×210 मे. वा.	जल तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राजस्थान बिजली बोर्ड द्वारा अभी और अन्वेषण किये जाने हैं । तदनुसार, उन्हें सलाह दी गई है कि आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित करने के बाद संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजी जायें संशोधित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।
4.	चित्तौड़गढ़ 2×210 मे. वा.	